

रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस०एम०/13-14/96.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बोरवार, 5 दिसम्बर, 1996/14 अग्रहायण, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 5 दिसम्बर, 1996

संख्या 1-63/96-वि० स०—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत "हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 1996

(1996 का विधेयक संख्यांक 31)" जो दिनांक 5 दिसम्बर, 1996 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

1996 का विधेयक संख्यांक 31.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 1996

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1996 है।

संक्षिप्त
नाम।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 की धारा 6-ग के स्पष्टीकरण में "अवयस्क बच्चे" शब्दों के स्थान पर "अविवाहित सन्तान" शब्द रखे जाएंगे।

धारा
6-ग का
संशोधन।

1971 का 8

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 की धारा 6-ग के अधीन भूतपूर्व विधान सभा सदस्य अपने लिए और अपने पति-पत्नी, अवयस्क बच्चे और माता-पिता जो पूर्णतः उस पर आश्रित हैं, के लिए चिकित्सा सुविधाओं का हकदार है। हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य सुख सुविधा समिति की सिफारिश पर, भूतपूर्व विधान सभा सदस्यों के अविवाहित पुत्र और पुत्रियों को, जो पूर्णतः उस पर आश्रित हैं, चिकित्सा सुविधाएं देने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मंत्री।

शिम ला:

5 दिसम्बर, 1996.

द्वितीय जापन

विधेयक के खण्ड 2 के अधिनियमित किए जाने पर, राजकोष से प्रतिवर्ष 0.50 लाख रुपये का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा। क्योंकि प्रस्तावित संशोधन भावी प्रभाव का है, इसलिए कोई अनावर्ती व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी जापन

-शून्य-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[सामान्य प्रशासन विभाग नस्ति संख्या जी० ए० डी०-सी० (पी० ए०) 4-21/94]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 1996 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 31 of 1996.

**THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY
(ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) SECOND
AMENDMENT BILL, 1996**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Act, 1996.

Short title

2. In section 6-C of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, in its Explanation, for the words “minor children”, the words “unmarried children” shall be substituted.

Amend men
of section
6-C.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under section 6-C of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, an ex-M. L. A. is entitled to medical facilities for himself and his spouse, minor children and parents, who are wholly dependant upon him. On the recommendation of the 'Members Amenities Committee of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha' it has been decided to grant medical facilities to the unmarried sons and daughters of ex-M. L. As., who are wholly dependant upon them. This has necessitated the amendment in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA:

The 5th December, 1996.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State exchequer to the tune of Rs. 0.50 lacs per annum. As the proposed amendment is prospective in effect, there will be no non-recurring expenditure.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[GAD FILE No. GAD-C (PA) 4-21/94]

The Governor of Himachal Pradesh after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill, 1996 recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.